

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes, Sir. A statement containing the major recommendations of the Committee is laid on the Table of the House.

(b) Government have decided to inform Samachar that they are in favour of restoring the status quo ante and therefore the revival of the four news agencies which existed prior to their merger on 24th January, 1976, namely, Press Trust of India, United News of India, Hindustan Samachar and Samachar Bharti.

#### Statement

The major recommendations of the Experts Committee on News Agencies are as follows :—

(a) Samachar should be split into two agencies, namely VARTA and SANDESH. While VARTA should provide and develop news supply in Hindi and at least 6 or 7 other Indian languages, along with an English service. SANDESH should be exclusively an English service. They should set up, in partnership, an international desk known as NEWS-INDIA for incoming and outgoing news which is visualised as full-fledged and growing international news cast. Correspondents and stringers should be established in about 25 places in the world over two years, as against 5 at present. Ministry of External Affairs should subscribe to its services to feed the Missions abroad.

(b) Out of 13 Members of the Governing Board of VARTA 9 should be drawn from subscribers of different languages and 4 from employees. There should be 2 co-opted Members chosen from the fields of education, culture etc. The Chief Editor would be an ex-officio Member. All of them would elect a Chairman. The Governing Body of Sandesh would be constituted on similar principles, while the Chairman would be part-time and honorary, the highest executive would be the Chief Editor. The Managing Committee of NEWS-INDIA would be constituted out of the Members of the two Boards. Every Member would have two year tenure.

(c) The structure would be provided under an Act of Parliament.

(d) The task of reorganisation should be given to an interim body to be appointed by Government. Legal steps should be taken to vest this body with authority.

(e) It is estimated that the whole structure would require an additional provisions of Rs. 170 lakhs per year.

(f) As for subscription rates, it is noted that the Samachar has already raised the subscription rates in many cases. However, the interim body has to review these rates. It has been recommended that Akashvani/Doordarshan should pay their subscription at the rate of Re. 1/- per radio licence and Rs. 5/- per TV licence. On the above formula, the existing AIR subscription of about Rs. 28 lakhs would be raised to nearly Rs. 198 lakhs. The subscription should be paid to VARTA and SANDESH in the ratio of 60 : 40.

#### बिहार में जल परिवहन

576. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या नौबहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य ने केन्द्र सरकार को बिहार में जल परिवहन के विकास के संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार का बिहार को कितनी धनराशि देने का विचार है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1976-77 और 1977-78 में जल परिवहन के विकास के लिए कोई धन राशि दी थी ?

नौबहन और परिवहन मंत्रालय से प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चाँद राय) :

(क) बिहार सरकार ने 10-10-77 को 1-4-78 से शुरू होने वाली अगली पंच-वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए पांच योजनाओं का सुझाव दिया है। राज्य सरकार से अभी तक कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अगली पंचवर्षीय योजना (1978-83) का निर्माण प्रगति पर है।

(ग) जी नहीं। 1976-77 तथा 1977-78 में जल परिवहन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को कोई राशि आवंटित नहीं की है।

### बिहार में नए उद्योग आरंभ करने की योजना

577. श्री शानेश्वर प्रसाद यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे चलाने के लिए कोई नई योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का 1977-78 और 1978-79 के दौरान इन उद्योगों के लिए कितनी धनराशि देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आशा मयती) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एटासिक एनर्जी एजेन्सी विद्याना के साथ भारी पानी के आयात के लिए करार

578. श्री यादबेन्द्र दत्त : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विद्याना से भारी पानी प्राप्त करने के लिए एटासिक एनर्जी एजेन्सी, विद्याना के साथ कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). भारी पानी के आयात के लिए भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, विद्याना के साथ कोई

करार नहीं किया है। तथापि, राजस्थान परमाणु बिजलीघर में इस्तेमाल होने वाले भारी पानी की सप्लाई के रूस द्वारा किए जाने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ सुरक्षा-व्यवस्था संबंधी एक करार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु, ऊर्जा आयोग द्वारा परमाणु बिजलीघर, कोटा को ईंधन की सप्लाई

579. श्री यादबेन्द्र दत्त : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में परमाणु बिजलीघर, कोटा, राजस्थान, को ईंधन सप्लाई करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, विद्याना के साथ कोई करार किया है और क्या सरकार की एक शर्त कि विदेशी एजेंसियों द्वारा भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निरीक्षण किया जा सकेगा, स्वीकार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या करार की एक प्रति, जिसमें स्वीकार की गई शर्तों का सक्षिप्त विवरण हो, लोक सभा के पटल पर रखी जाएगी ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के लिए ईंधन की सप्लाई के संबंध में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ हाल में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, राजस्थान परमाणु बिजलीघर में इस्तेमाल होने वाले भारी पानी की सप्लाई रूस द्वारा की जाने के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ एक सुरक्षा व्यवस्था संबंधी एक करार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।